



सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रेन: ILO-UNICEF

प्रलिस के लयि:

सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रेन, ILO, UNICEF, कोवडि-19, गरीबी, SDG, बच्चों के लयि PM CARES ।

मेन्स के लयि:

सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रेन: ILO-UNICEF ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [अंतरराष्ट्रीय शरम संगठन \(International Labour Organization- ILO\)](#) और [संयुक्त राषट्र बाल कोष \(United Nations Children's Fund- UNICEF\)](#) ने एक रपिर्ट जारी की है जसिका शीर्षक है- **“More than a billion reasons: The urgent need to build universal social protection for children”**, जसिके अनुसार, 4 में से सरिफ 1 बच्चा सामाजकि सुरक्षा द्वारा पररिक्षति है, जबकि शेष अन्य बच्चे गरीबी, बहषिकरण और बहुआयामी अभाव के शकार हो जाते हैं ।

सामाजकि सुरक्षा की आवश्यकता:

- सामाजकि सुरक्षा एक सार्वभौमकि मानव अधिकार है और गरीबी से मुक्त दुनयि हेतु एक पूरव शरत है ।
- यह दुनयि के सबसे कमजोर बच्चों को क्षमता प्राप्त करने में मदद देने का एक महत्त्वपूर्ण आधार भी है ।
- सामाजकि सुरक्षा भोजन, पोषण, शकिषा और स्वास्थय सेवा तक पहुँच बढ़ाने में मदद करती है ।
- यह [बाल शरम](#) और [बाल वविाह](#) को रोकने में भी मदद कर सकती है एवंलैंगकि असमानता तथा बहषिकार में अंतरनहिति कारणों को भी दूर कर सकती है ।
- यह घरेलू आजीविका का समर्थन करते हुए तनाव और यहाँ तक कि घरेलू हसिा को भी कम कर सकती है ।
- यह आर्थकि गरीबी को खतम कर उस कलंक और बहषिकरण को भी कम कर सकती है जसिका सामना कई गरीब बच्चे करते हैंसाथ ही बचपन में महसूस की गई वंचना को "कम-से-कम" करने में मदद कर सकती है ।

रपिर्ट के नषिकर्ष:

■ समग्र परदृश्य:

- 0-18 वर्ष की आयु के 1.77 बलियन बच्चों के लयि पारवारिकि नकद लाभ उपलब्ध नहीं है जो सामाजकि सुरक्षा प्रणाली का एक मौलकि सत्भ है ।
- वयस्कों की तुलना में बच्चों के अत्यधिक गरीबी में रहने की संभावना दोगुनी होती है ।
- लगभग 800 मलियन बच्चे 3.20 अमेरकि डॉलर प्रतदिनि की गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं और 1 बलियन बच्चे बहु-आयामी गरीबी का सामना कर रहे हैं ।
- 0-15 वर्ष की आयु के केवल 26.4% बच्चों को सामाजकि सुरक्षा द्वारा पररिक्षति कयिा जा सका है, शेष 73.6% बच्चे गरीबी, बहषिकरण (Exclusion) एवं बहुआयामी अभावों में जी रहे हैं ।
- वशिव स्तर पर सभी 2.4 बलियन बच्चों को स्वस्थ और खुश रहने के लयि सामाजकि सुरक्षा की आवश्यकता होती है ।

■ सामाजकि सुरक्षा कवरेज:

- वर्ष 2016 से 2020 के मध्य वशिव के हर कषेत्र में बाल और परवार सामाजकि सुरक्षा कवरेज दर गरि गई या फरि स्थरि हो गई, जसिसे कोई भी देश वर्ष 2030 तक पर्याप्त सामाजकि सुरक्षा कवरेज के तहत [सतत वकिस लकष्यों \(SDG\)](#) को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता ।

- लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों में कवरेज लगभग 51% से घट कर 42% हो गया है।
- कई अन्य क्षेत्रों में कवरेज या तो स्थिर है या इसमें कमी आई है।

■ प्रभाव:

- अत्यधिक संकट के कारण **बड़ी संख्या में बच्चों के गरीबी में होने की** आशंका है, जिस वजह से सामाजिक सुरक्षा उपायों में तत्काल वृद्धि किये जाने की आवश्यकता होगी।
- बच्चों के लिये सामाजिक सुरक्षा की कमी के तत्काल और दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं, इससे बाल श्रम एवं बाल विवाह जैसे अधिकारों के उल्लंघन की व्यापकता बढ़ जाती है, जिससे बच्चों की आकांक्षाओं तथा अवसरों में भी कमी आती है।
- इसके अतिरिक्त इस अवास्तविक मानव क्षमता का सामान्य रूप से समुदाय, समाज और अर्थव्यवस्था पर अपरिहार्य प्रतिकूल तथा दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।

■ सामाजिक सुरक्षा का महत्त्व:

- **कोविड-19 महामारी** से पूर्व वयस्कों की तुलना में बच्चों के अत्यधिक गरीबी में रहने की संभावना दोगुनी से अधिक थी।
- एक अरब बच्चे गरीबी के कई रूपों का अनुभव करते हैं जिनकी भोजन, पानी, स्वच्छता, आवास, स्वास्थ्य देखभाल, स्कूली शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं तक पहुँच की कमी है।
- कोविड-19 महामारी ने संकट के समय में सामाजिक सुरक्षा के महत्त्व को प्रदर्शित किया।
- विश्व की लगभग प्रत्येक सरकार ने बच्चों और परिवारों की मदद करने के लिये या तो मौजूदा कार्यक्रमों का तेज़ी से अनुकूलन किया या **नई सामाजिक सुरक्षा पहल** की शुरुआत की।

- **अनाथों तथा बच्चों की बाल सहायता अनुदान (सीएसजी) राशि** बढ़ाने के लिये दक्षिण अफ्रीका ने वर्ष 2022 में एक कल्याणकारी योजना बाल सहायता अनुदान (सीएसजी) टॉप-अप कार्यक्रम की शुरुआत की।
- राष्ट्रीय **"पीएम केयरस फॉर चिल्ड्रन"** योजना 10,793 पूरण अनाथों और 151,322 अर्द्ध-अनाथों के लिये उपायों का पैकेज है, जिससे 31 भारतीय राज्यों में अधिनियमित किया गया था। अब तक 4,302 बच्चे इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं।

सुझाव:

- सभी बच्चों के लिये सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दशा में कार्रवाई करना नीति निर्माताओं हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिये, जिनमें उन कार्यक्रमों में भी शामिल किया जाना चाहिये जो बाल गरीबी की समस्या के समाधान की गारंटी प्रदान करते हैं।
- अधिकारियों को राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के माध्यम से बाल लाभ प्रदान करने की भी सलाह दी जाती है जो परिवारों को महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं से जोड़ती हैं, जैसे गुणवत्ता वाली मुफ्त या सस्ती बाल-देखभाल।
- **घरेलू संसाधनों को जुटाकर** बच्चों के लिये बजट आवंटन बढ़ाकर, माता-पिता एवं अभिभावकों हेतु सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करके और अच्छे काम एवं पर्याप्त कर्मचारी लाभ की गारंटी देकर योजनाओं के लिये **स्थायी वित्तपोषण हासिल करने** की आवश्यकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मलेन 138 और 182 (2018) से संबंधित हैं:

- (a) बाल श्रम
- (b) वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिये कृषि प्रथाओं की अनुकूलता
- (c) खाद्य कीमतों और खाद्य सुरक्षा का वनियमन
- (d) कार्यस्थल पर लिंग समानता

उत्तर: (a)

स्रोत : डाउन टू अर्थ